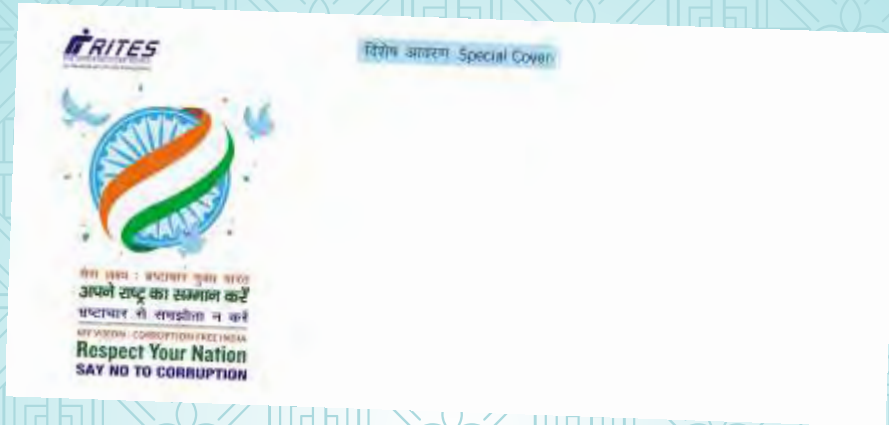


सतर्कता बुलेटिन VIGILANCE BULLETIN

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
30 अक्टूबर से 04 नवम्बर 2017

VIGILANCE AWARENESS WEEK

30th October to 4th November 2017





Sardar Vallabh Bhai Patel

(31.10.1875 to 15.12.1950)

**Vigilance awareness week is observed
every year as a mark of respect to
Sardar Vallabh Bhai Patel**

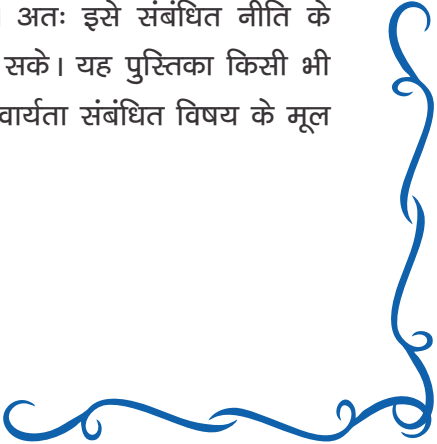


DISCLAIMER

The handbook is only indicative and is by no means exhaustive, nor is it intended to be a substitute for rules, procedures and existing instructions / guidelines on the subject. The contents herein do not in any way supersede the rules contained in any of the CVC / RAILWAY / RITES CODES and should be read with relevant policy circulars for proper appreciation of the issues involved. This handbook also should not be produced in any court of law and whenever necessary, reference should always be made to the original orders on the subject. The primary purpose of the handbook is for reference only.

अस्वीकरण

यह पुस्तिका केवल सांकेतिक है तथा किसी भी रूप में यह सर्वांगीण नहीं है और न ही विषयक नियमों, प्रक्रियाओं तथा वर्तमान अनुदेशों/दिशानिर्देशों का प्रतिस्थापन है और न ही इसमें दी गई विषयवस्तु किसी भी रूप में सीवीसी/रेलवे/राइट्स संहिता के किसी नियम का अधिक्रमण करती है। अतः इसे संबंधित नीति के परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए ताकि संगत मामले को वास्तविक रूप में समझा जा सके। यह पुस्तिका किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो वहां अनिवार्यता संबंधित विषय के मूल आदेशों का संदर्भ लेना चाहिए। इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य केवल संदर्भ मात्र है।



Integrity Pledge

For individual citizens

I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption.

I, therefore, pledge:

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behavior;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.

नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है. मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है.

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए.

अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा;
- ना तो रिश्वत लूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा;
- जनहित में कार्य करूंगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा;

Integrity Pledge for Organizations

We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. We believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost strictness.

We realize that as an Organization, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations.

We, therefore, pledge that:

- We shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity;
- We shall not offer or accept bribes;
- We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness;
- We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business;
- We shall adopt a code of ethics for all our employees;
- We shall sensitise our employees of laws, regulations etc. relevant to their work for honest discharge of their duties;
- We shall provide grievance redressal and Whistle Blower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities;
- We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large.

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हमें अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करनी होगी।

मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि:-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे;
- हम न तो रिश्तत लेंगे और न ही रिश्तत देंगे;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे;

MESSAGE

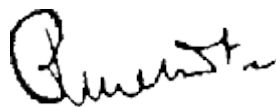


Rajeev Mehrotra

As per the directives of Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week is being observed this year from 30th October 2017 to 04th November 2017. The theme of Vigilance Awareness Week is “ **My vision- Corruption Free India** ”. RITES Vigilance is organizing various programs on this occasion. I am very happy to note that Vigilance functionaries under the guidance of Chief Vigilance Officer have compiled Vigilance Bulletin to improve transparency into working. I hope that these case studies would be beneficial to all the employees of RITES. Every RITES employee should carefully read this book as it would be very helpful to them.

I applaud the efforts made by Vigilance team in bringing out this book.

With best Wishes,

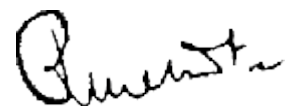


(Rajeev Mehrotra)
Chairman and Managing Director

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के अनुसार इस वर्ष 30 अक्टूबर 2017 से 04 नवंबर 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय “मेरा लक्ष्य- भ्रष्टाचार मुक्त भारत” है. इस अवसर पर राइट्स सतर्कता विभाग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में सतर्कता कर्मियों ने कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सतर्कता बुलेटिन का संकलन किया है. मुझे आशा है कि यह केस अध्ययन पुस्तिका राइट्स के सभी कर्मियों के लिए लाभप्रद होगी. प्रत्येक राइट्स कर्मचारी को यह पुस्तिका ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए. यह उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी.

इस पुस्तिका के प्रकाशन के लिए सतर्कता टीम का प्रयास अत्यंत सराहनीय है.

शुभकामनाओं सहित



(राजीव मेहरोत्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

MESSAGE



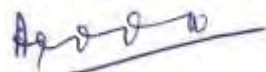
Ashok Kumar Poddar

Vigilance Awareness Week is being observed this year from 30th October to 4th November 2017. The theme chosen for Vigilance Awareness Week is “MY vision – Corruption Free India”.

Corruption is a drag in the development of any country. It is an established fact that countries where integrity level is high, progress is swift. To achieve the vision of corruption free India means faster growth resulting in elimination of poverty and happy citizens.

Taking a cue from last year, we are bringing out a Vigilance Bulletin on case studies based upon the experience in preventive and CTE type checks done by Vigilance Division. We have also included articles received from personnel in various offices of the company. I am sure the Bulletin shall be an useful guidance to personnel in better performance.

We shall be happy to receive your comments and suggestions so that the Bulletin in 2018 can be made more relevant.



(Ashok Kumar Poddar)
Chief Vigilance Officer

इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2017 तक मनाया जा रहा है. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए "मेरा लक्ष्य - भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय को चुना गया है.

भ्रष्टाचार किसी भी देश के विकास में एक बाधा है. यह सर्वथा सिद्ध है कि जिस राष्ट्र में सत्यनिष्ठा का स्तर उंचा होता है वह राष्ट्र तेजी से विकास करता है. भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ है- गरीबी का उन्मूलन तथा खुशहाल जन-जीवन.

पिछले वर्ष की भांति, हम सतर्कता विभाग द्वारा की गई निवारक जाँच तथा सीटीई जाँच के अनुभवों के आधार पर केस अध्ययन संबंधी सतर्कता बुलेटिन प्रकाशित कर रहे हैं. हमने कंपनी के विभिन्न कार्यालयों के कर्मियों से प्राप्त लेखों को भी इस बुलेटिन में शामिल किया है. मुझे विश्वास है कि यह बुलेटिन कर्मियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करेगा.

हम आपकी प्रतिक्रिया व सुझावों का स्वागत करते हैं, इससे हम 2018 में बुलेटिन को अधिक प्रासंगिक बनाने में सफल होंगे.



(अशोक कुमार पोद्दार)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

MESSAGE



Arbind Kumar

I am very happy to note that Vigilance Wing of RITES is bringing out this hand book of Case studies on the Occasion of Vigilance Awareness Week. I am sure the publication of this book will bring into focus the perspectives in proper dealing with tenders and minimize incidence of omissions to a large extent.

I request all concerned to study this book carefully and understand the shortcomings pointed out in the case studies to benefit the organization and themselves. I congratulate the Vigilance department of RITES for undertaking this task of bridging the gap of knowledge about vigilance matters.



(Arbind Kumar)
Director Projects

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राइट्स का सतर्कता विंग सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर केस अध्ययन पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है. मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से भविष्य में निविदाओं संबंधी कार्यों को सही रूप में करने में मदद मिलेगी तथा इस संबंध में होने वाली चूकों में काफी हद तक कमी आएगी.

मैं सभी संबंधितों से आग्रह करता हूँ कि इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा संगठन और स्वयं के हित में केस अध्ययनों में बताई गई कमियों को समझें. मैं, सतर्कता मामलों के बारे में ज्ञान के बीच अंतर को पूरा करने संबंधी इस प्रयास के लिए राइट्स के सतर्कता विभाग को बधाई देता हूँ.



(अरबिंद कुमार)
निदेशक परियोजना

MESSAGE



Ajay Gaur

This year the theme declared by the Central Vigilance Commission is 'My vision – Corruption Free India'. Corruption is a menace which has to be uprooted if we have to realize the full fruits of our efforts.

Due to the constant effort made by the CVC, there has been widespread awareness against corruption. Attempting to create an environment for a corruption free society is a big and timely step.

While RITES is making steady progress in terms of its financials, our team of officers and staff, and Vigilance Cell in particular, are making every effort to keep corruption at bay.

I am happy that RITES is bringing out Vigilance Bulletin in connection with Vigilance Awareness Week 2017. The bulletin, compiled under the leadership Sh A. K. Poddar, CVO will be of immense practical help for the officers engaged in various business activities of RITES.



(Ajay Gaur)
Director Finance

इस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा घोषणा किया गया विषय है- 'मेरा लक्ष्य- भ्रष्टाचार मुक्त भारत'. भ्रष्टाचार एक ऐसा खतरा है जिसे समूल उखाड़े जाने की जरूरत है; तभी हमारे प्रयास पूरी तरह फलीभूत होंगे.

केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न हुई है. ऐसा माहौल तैयार करना जिससे समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो, एक बड़ा व समय पर उठाया गया कदम है.

राइट्स अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में प्रगति कर रहा है और हमारी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम, और विशेष रूप से सतर्कता सेल, भ्रष्टाचार को दूर रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

मुझे खुशी है कि राइट्स सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के अवसर पर सतर्कता बुलेटिन प्रकाशित कर रहा है. श्री ए.के. पौडार, सीवीओ, के नेतृत्व में संकलित बुलेटिन, राइट्स की विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े, अधिकारियों के लिए व्यवहारिक रूप से बहुत उपयोगी होगी.



(अजय गौड़)
निदेशक वित्त

MESSAGE



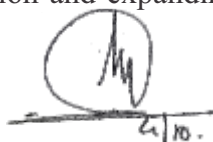
Mukesh Rathore

Vigilance is an integral part of the management. It provides important instruments for improving performance of an organization. This includes promoting clean business transactions, professionalism, productivity, promptness and ethical practices. It also assists in systemic improvements in curbing malpractices for corruption. Therefore, vigilance helps in improving efficiency and effectiveness of the personnel as well as the organization.

I would urge upon all to become vigilant by identifying deficiencies which provide opportunities for malpractices and corruption so that such opportunities are curbed. Thus every Individual can play an important role in the organizational interest. Such actions bring joys and successes to the organisation in creating ethical and healthy work culture

Let us follow four cardinal principles of vigilance i.e. Transparency, Fairness, Competitiveness & Accountability.

On the occasion of “Vigilance Awareness Week”, I would like to persuade and encourage everyone to join hands in rooting out corruption and expanding integrity.



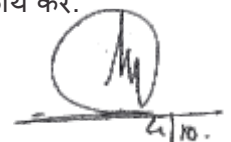
(Mukesh Rathore)
Director Technical

सतर्कता, प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है. यह किसी संगठन के निष्पादन को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसमें स्वच्छ व्यापार लेनदेन, व्यावसायिकता, उत्पादकता, मुस्तैदी और नैतिकतापूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना शामिल है. इससे भ्रष्टाचार संबंधी कृत्यों को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधार लाने में भी सहायता मिलती है. इसलिए सतर्कता, कर्मियों के साथ-साथ संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने में सहायक है.

मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे सतर्क रहें तथा उन कमियों की पहचान करें जिनसे अनाचार व भ्रष्टाचार पनपता है ताकि इसकी संभावना ही न रहे. इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति संगठन के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. ऐसे क्रियाकलापों से संगठन को प्रसन्नता व सफलता की अनुभूति होती है और नैतिकतापूर्ण व स्वस्थ कार्य संस्कृति का सृजन होता है.

आइए, हम सतर्कता के चार मुख्य सिद्धांतों पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और जवाबदेही का पालन करें.

"सतर्कता जागरूकता सप्ताह" के अवसर पर, मैं चाहता हूं कि आप सभी भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर उत्साहपूर्वक कार्य करें.



(मुकेश राठौर)
निदेशक तकनीकी

No. 004/VGL/18
Government of India
Central Vigilance Commission

Satarkata Bhawan, Block-A,
GPO Complex, INA,
New Delhi-110023.
Dated: 13th April, 2004

Office Order No. 23/04/04

(read with modification vide office Order No. 74/12/05)

Subject: Vigilance angle – definition of.

As you are aware, the Commission tenders advice in the cases, which involve a vigilance angle. The term “vigilance angle” has been defined in the Special Chapters for Vigilance Management in the public sector enterprises, public sector banks and public sector insurance companies. The matter with regard to bringing out greater quality and precision to the definition has been under reconsideration of the Commission. The Commission, now accordingly, has formulated a revised definition of vigilance angle as under:

“Vigilance angle is obvious in the following acts: -

- (i) Demanding and/or accepting gratification other than legal remuneration in respect of an official act or for using his influence with any other official.
- (ii) Obtaining valuable thing, without consideration or with inadequate consideration from a person with whom he has or likely to have official dealings or his subordinates have official dealings or where he can exert influence.
- (iii) Obtaining for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage by corrupt or illegal means or by abusing his position as a public servant.
- (iv) Possession of assets disproportionate to his known sources of income.
- (v) Cases of misappropriation, forgery or cheating or other similar criminal offences.

2(a)** There are, however, other irregularities where circumstances will have to be weighed carefully to take a view whether the officer's integrity is in doubt. Gross or willful negligence; recklessness in decision making; blatant violations of systems and procedures; exercise of discretion in excess, where no ostensible/public interest is evident; failure to keep the controlling authority/superiors informed in time – **these are some of the irregularities where the disciplinary authority with the help of the CVO should carefully study the case and weigh the circumstances to come to a conclusion whether there is reasonable ground to doubt the integrity of the officer concerned.**

2(b) **Any undue/ unjustified delay in the disposal of a case, perceived after considering all relevant factors, would reinforce a conclusion as to the presence of vigilance angle in a case.**

****as modified vide Office Order No. 74/12/05 dated the 21/12/05.**

3. The raison d'être of vigilance activity is not to reduce but to enhance the level of managerial efficiency and effectiveness in the organization. Commercial risk taking forms part of business. Therefore, every loss caused to the organization, either in pecuniary or non-pecuniary terms, need not necessarily become the subject matter of a vigilance inquiry. Thus, whether a person of common prudence, working within the ambit of the prescribed rules, regulations and instructions, would have taken the decision in the prevailing circumstances in the commercial/operational interests of the organization is one possible criterion for determining the bonafides of the case. A positive response to this question may indicate the existence of bonafides. A negative reply, on the other hand, might indicate their absence.

4. Absence of vigilance angle in various acts of omission and commission does not mean that the concerned official is not liable to face the consequences of his actions. **All such lapses not attracting vigilance angle would, indeed, have to be dealt with appropriately as per the disciplinary procedure under the service rules.”**

5. The above definition becomes a part of the Vigilance Manual and existing Special Chapter on Public Sector Banks and Public Sector Enterprises brought out by the Commission, in supersession of the existing definition.

CVOs may bring this to the notice of all concerned.

Sd/-
(Anjana Dube)
Deputy Secretary

All Chief Vigilance Officers

COMMON IRREGULARITIES IN PROJECT EXECUTION

Payment for steel reinforcement

During various CTE type checks conducted by RITES Vigilance, it has been observed that payments for steel reinforcement are being made as per standard coefficients of unit weight of steel. However, as per specifications, payment for steel is to be made considering lesser of the standard and actual unit weight coefficient. By not using lesser of actual unit weight and standard unit weight of steel reinforcement, in some cases there have been excess payment to contractor. All site executives should therefore be careful regarding above matter while making payment of steel reinforcement to contractor.

Maintenance of record of material at site

During examination of one of the works undertaken by RITES, the CTE of Central Vigilance Commission had observed as under:

“Records of materials received like DAP, Lindane, Cholorpyrophos etc. were being maintained but there were no records of materials issued/consumed at site in the material register.”

In this connection, all the site executive should follow para 20.15 of 'RITES Guidelines on Construction Project Management' where it is, inter-alia, laid down that in case of items involving use of paints and chemicals whose quality and consumption have to be kept under close watch, their record may be maintained in the form of register in the proforma given at Annexure 20.14 although the material is to be supplied by the contractor. All the site executives should therefore strictly adhere to instructions given in para 20.15 of RITES CPM Guidelines and maintain 'Materials at Site' (MAS) register in the proforma given in Annexure 20.14 of Guidelines.



**“Honesty is the first chapter in the book of wisdom”
- Thomas Jefferson**



परियोजना निष्पादन में सामान्य अनियमितताएं

पोषण इस्पात (टीएमटी बारस) के लिए भुगतान

राइट्स सतर्कता द्वारा आयोजित विभिन्न सीटीई प्रकार के निरीक्षणों के दौरान यह देखा गया है कि पोषण इस्पात के लिए भुगतान स्टील के इकाई भार के मानक गुणांक के अनुसार किया जा रहा है। तथापि, विनिर्देशों के अनुसार, मानक और वास्तविक इकाई भार गुणांक में से कम के आधार पर स्टील के लिए भुगतान करना होता है। पोषण इस्पात के वास्तविक यूनिट भार और मानक इकाई भार के कम का उपयोग न करके, कुछ मामलों में ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान किया गया है। ठेकेदार को पोषण इस्पात का भुगतान करते समय सभी साइट अधिकारियों को उपर्युक्त मामले के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए।

साइट पर सामग्री के रिकॉर्ड का रखरखाव

राइट्स द्वारा किए जा रहे कार्यों में से किसी एक की जांच के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सीटीई विभाग ने पाया कि:

"डीएपी, लिंडेन, क्लोरीपीरोफॉस आदि जैसी प्राप्त की गई सामग्रियों का रिकॉर्ड रखा गया था; किंतु साइट पर जारी की गई/ उपभोग की गई सामग्रियों का सामग्री रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।"

इस संबंध में, सभी साइट अधिकारियों को 'निर्माण परियोजना प्रबंधन पर राइट्स दिशानिर्देश' के पैरा 20.15 का पालन करना चाहिए, जहां यह अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित है कि पेंट और रसायनों का उपयोग करने वाली मर्दों के मामले में जिसकी गुणवत्ता और खपत पर कड़ी नजर रखी जानी आवश्यक है, उनके रिकॉर्ड अनुबंध 20.14 में दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर के रूप में बनाए जा सकते हैं। हालांकि, सामग्री की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाती है। इसलिए सभी साइट अधिकारियों को राइट्स सीपीएम दिशानिर्देशों के पैरा 20.15 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और दिशानिर्देशों के अनुलग्नक 20.14 में दिए गए प्रोफार्मा में 'साइट पर सामग्री' (एमएस) रजिस्टर बनाए रखना चाहिए।

"ईमानदारी बुद्धिमत्ता की किताब का पहला अध्याय है"
- थॉमस जेफरसन

Cement content in design mix concrete

During examination of one of the works executed by RITES, the Vigilance Department has observed that a certain quantity of cement was adopted on the basis of mix design which was got done from an engineering college. However, when cement concrete cubes were routinely tested at site, it was noticed that by adopting the said design mix, the strength of concrete was consistently coming much higher than the specified design strength. The quantity of cement could have been reduced and not doing so has resulted in wasteful usage of cement. Thus technical authorities posted at project sites should ensure that the concrete mix design obtained from engineering college/ research laboratory etc. should be tested at site and modified suitably, if required so as to obtain the specified strength in an economical manner. Further, it should be ensured that a provision for recovery of cost of cement is made in the contract in case as per design mix/ actual mix, the quantity of cement per cum of concrete is less than that specified in the BOQ item of the contract.

Use of TMT steel and structural steel (Brand specified in contract)

RITES Vigilance carried out a CTE Type check of one of the works in 2016. During scrutiny of contract documents, it was noticed that the contractor was supposed to use TMT bars and Structural Steel from TATA, RINL, SAIL and Vizag Steel. The contractor was allowed use of TMT steel and structural steel from un-approved brand without any valid reason. The procurement challans available at site were examined and it was found that the procured steel was cheaper than the steel specified in the contract. The use of non-approved brand of steel was allowed at site without knowledge and approval of the competent authority. The technical authorities had also not carried out cost corrections, prior to allowing use of un-approved brand of steel. Thus by doing so, financial benefit was extended to the working contractor.



“To believe in something and not to live it, is dishonest”

- Mahatma Gandhi



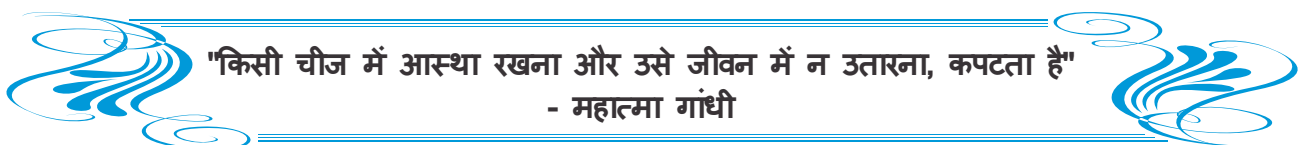
डिजाइन मिश्रित कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा

राइट्स द्वारा निष्पादित एक कार्य की जांच के दौरान सतर्कता विभाग ने पाया कि किसी इंजीनियरी कॉलेज से तैयार कराए गए मिश्रण के डिजाइन के आधार पर कुछ मात्रा में सीमेंट को अपनाया गया था. तथापि, जब सीमेंट कंक्रीट क्यूब्स का साइट पर नेमी परीक्षण किया गया तो यह देखा गया कि कथित डिजाइन मिश्रण को अपनाने से, कंक्रीट की क्षमता विनिर्दिष्ट डिजाइन क्षमता से बहुत अधिक आ रही थी. सीमेंट की मात्रा कम की जा सकती थी और ऐसा न करने का अर्थ था कि सीमेंट व्यर्थ में ही प्रयोग में लाई जा रही थी. इसलिए परियोजना स्थलों पर तैनात तकनीकी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंजीनियरी कॉलेज/ शोध प्रयोगशाला आदि से प्राप्त कंक्रीट मिक्स डिजाइन का साइट पर परीक्षण किया जाये और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए, ताकि किफायती ढंग से निर्दिष्ट क्षमता प्राप्त हो सके. इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुबंध में यह प्रावधान हो कि डिजाइन मिश्रण/वास्तविक मिश्रण के अनुसार कंक्रीट की मात्रा के अनुपात में सीमेंट की मात्रा अनुबंध के बीओक्यू में विनिर्दिष्ट से कम पाए जाने पर सीमेंट की लागत की वसूली की जा सके.

टीएमटी स्टील और स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल

(अनुबंध में विनिर्दिष्ट ब्रांड)

राइट्स सतर्कता ने 2016 में एक कार्य की सीटीई प्रकार की जांच की. ठेके दस्तावेजों की जांच के दौरान यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा टाटा, आरआईएनएल, सेल और विजाग स्टील का टीएमटी बार और संरचनात्मक स्टील का प्रयोग किया जाना था. किसी भी वैध कारण के बिना ठेकेदार को गैर-अनुमोदित ब्रांड का टीएमटी स्टील और संरचनात्मक स्टील उपयोग करने की अनुमति दी गई. साइट पर उपलब्ध चालान की जांच की गई और यह पाया गया कि खरीदा गया स्टील अनुबंध में विनिर्दिष्ट स्टील से सस्ता था. गैर-अनुमोदित ब्रांड के उपयोग को सक्षम प्राधिकारी के बिना संज्ञान और अनुमोदन के साइट पर अनुमति दी गई थी. तकनीकी अधिकारियों ने स्टील के गैर-अनुमोदित ब्रांड का उपयोग करने से पहले लागत में सुधार नहीं किया था. इस प्रकार ऐसा करके, कार्यरत ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहुंचाया गया.



Working rate for item in bill of quantity

During intensive examination of a work being executed by RITES, CTE noticed that there were three items under different sub-heads in the bill of quantity for supply of moorum. The estimated rates of all the three items were same. During the bidding process, the bidders were allowed to quote separate rates for the above three items. It was noticed that the lowest evaluated bidder quoted separate rates for all the three items. In the two items the quoted rates were less than the estimated rates but in one of the items, the rate quoted by the lowest bidder was about 90% above estimated rate. The three items were almost identical except the place where they were to be operated. The payment of moorum was made to the agency as per the usage of the item in the work. Thus the item of moorum with higher rate was also operated and payments were made to contractor on higher quoted rates in the Bill Of Quantities (BOQ) and according to CTE, overpayments were made to the agency on above account. While framing a Non-Schedule item, duplication of item needs to be avoided to prevent such instances in future.



मात्रा बिल (बिल ऑफ क्वांटिटीज़) में मदों की कार्य दर

राइट्स द्वारा निष्पादित किए जा रहे एक कार्य की गहन जांच के दौरान, सीटीई ने पाया कि मूरम की आपूर्ति के लिए मात्रा बिल में अलग-अलग उप शीर्षकों के अधीन तीन मदें थीं। तीनों मदों की अनुमानित दरें समान थीं। बोली प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाताओं को तीनों मदों के लिए अलग अलग दरों का उल्लेख करने की अनुमति दी गई थी। यह देखा गया कि सबसे कम मूल्यांकन वाले बोलीदाता ने सभी तीन मदों के लिए अलग दरों का उल्लेख किया। दो मदों में उल्लिखित दरें अनुमानित दरों से कम थीं लेकिन एक मद में, सबसे कम बोलीदाता द्वारा उल्लिखित दर अनुमानित दर से ९०% अधिक थी। तीनों मदें लगभग एक समान ही थीं सिवाय इसके कि जहां वे क्रियान्वत होनी थीं। कार्य में मद के उपयोग के अनुसार मूरम का भुगतान एजेंसी को किया गया था। इस प्रकार उच्च दर वाले मूरम की मद भी क्रियान्वयन में आई थी और ठेकेदार को मात्रा बिल (बीओक्यू) में उल्लिखित उच्च दरों पर भुगतान किया गया था और सीटीई के अनुसार, उपरोक्त कारण एजेंसी को अधिक भुगतान किया गया। भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए गैर-अनुसूची मद तैयार करते समय मद की पुनरावृत्ति से बचने की आवश्यकता है।

“ईमानदार लोग अपने कृत्यों को नहीं छिपाते”
-एमिली ब्रॉट

COMMON IRREGULARITIES IN INSPECTION OF MATERIALS

Inspection at a place not mentioned in the Purchase Order

In a preventive check regarding inspection of textile items, it came to notice that Inspecting Engineer carried out the inspection at a place which was not mentioned in the inspection clause of Purchase Order (PO). Inspecting Engineer (IE) failed to check the inspection clause included in the PO and conducted inspection in collusion with the vendor.

After investigation, it was noticed that while uploading the PO in RITES Inspection and Billing Monitoring system, vendor had not uploaded that part of the PO in which place of inspection was mentioned and thus misguided the Inspecting Engineer.

Lesson: Inspecting Engineer should check the uploaded Purchase Order thoroughly and match it with the original Purchase Order before inspection.

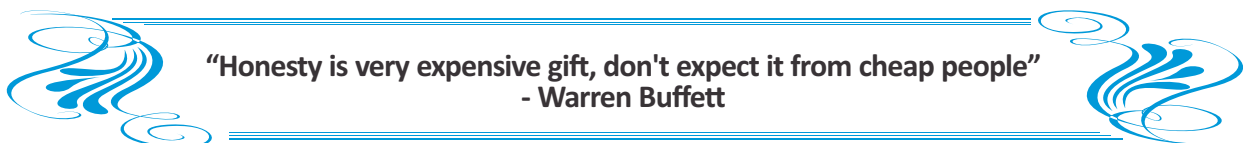
Inspection without full quantity of offered material

In a preventive check it was found that the Inspecting Engineer had conducted inspection of Equalizing Stays (Safety item) without ensuring availability of full quantity of offered material at the site of inspection. Inspecting Engineer had handed over RITES Holograms to the supplier, who in turn pasted the holograms on available quantity (666 Nos.) of the material.

During the check, only 666 nos. Equalizing Stays were found available at the place of inspection (duly affixed with RITES Hologram), instead of 2288 Nos. offered as per inspection call letter. 1300 Nos. unused holograms were found under custody of supplier and remaining holograms found given to supplier's sister concern where galvanizing process was being carried out.

Lesson: (i) Inspection should be started only after the Inspecting Engineer has physically ensured that the full offered quantity is available at the site of inspection

ii) RITES Holograms/Seal should not be handed over to supplier.



सामग्री के निरीक्षण में सामान्य अनियमितताएं क्रय आदेश में न लिखे गए स्थान पर निरीक्षण

टेक्सटाइल वस्तुओं के निरीक्षण की निवारक जांच में यह देखा गया कि निरीक्षण इंजीनियर ने उस जगह पर निरीक्षण किया जिसका क्रय आदेश (पीओ) के निरीक्षण क्लॉज में उल्लेख नहीं था. निरीक्षण इंजीनियर (आईई) ने पीओ अंकित निरीक्षण क्लॉज की अनदेखी करते हुए विक्रेता के साथ साँठ-गाँठ कर निरीक्षण किया.

जांच के बाद यह पाया गया कि राइट्स निरीक्षण और बिलिंग मॉनिटरिंग सिस्टम में पीओ अपलोड करते समय, विक्रेता ने पीओ के पृष्ठ को अपलोड नहीं किया था जिसमें निरीक्षण के स्थान का उल्लेख किया गया था और इस प्रकार निरीक्षण इंजीनियर को गुमराह किया गया था.

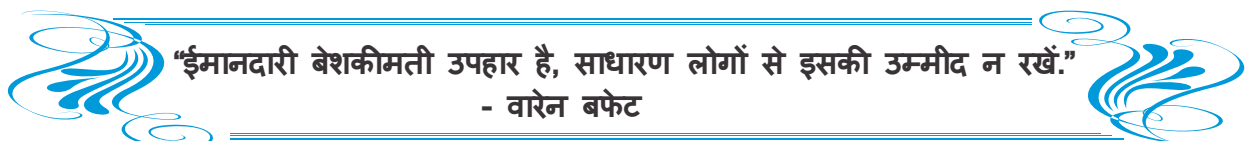
सीख : निरीक्षण करने वाले इंजीनियर को अपलोड किए गए क्रय आदेश की अच्छी प्रकार जांच करनी चाहिए तथा निरीक्षण से पूर्व इसका मिलान मूल क्रय आदेश से कर लेना चाहिए.

ऑफर की गई सामग्री की पूरी मात्रा के बिना निरीक्षण

एक निवारक जांच में यह पाया गया कि निरीक्षण इंजीनियर ने निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत की गई सामग्री की पूरी मात्रा की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना इक्वलाइजिंग स्टे (सुरक्षा मद) का निरीक्षण किया था. निरीक्षण इंजीनियर ने आपूर्तिकर्ता को राइट्स होलोग्राम सौंप दिए थे, जिसके फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता ने उपलब्ध सामग्री (६६६) पर होलोग्राम चिपका दिए थे. जांच के दौरान, २२८८ के स्थान पर निरीक्षण स्थल पर केवल 666 इक्वलाइजिंग स्टे (राइट्स होलोग्राम के साथ) पाए गए. 1300 अप्रयुक्त होलोग्राम आपूर्तिकर्ता के कब्जे में पाए गए तथा शेष होलोग्राम आपूर्तिकर्ता की सहयोगी संस्था को दिए गए पाए गए थे, जहां गैल्वनाइजिंग प्रक्रिया चल रही थी.

सीख : (i) निरीक्षण इंजीनियर द्वारा निरीक्षण स्थल पर पूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात ही निरीक्षण आरंभ करना चाहिए.

(ii) किसी भी परिस्थिति में राइट्स होलोग्राम/सील आपूर्तिकर्ता को नहीं सौंपे जाने चाहिए.



Forged internal reports and improper lab test requests

In a preventive check, it came to notice that supplier had submitted forged internal lab reports to the Inspecting Engineer and the inspection was carried out without reviewing the internal test reports. Further, Samples were sent to lab for testing. The request letter written to the lab however, did not specify all the tests that were required to be carried as per PO. Thus Inspecting Engineer had conducted the inspection in a casual way which resulted in passing of sub standard material.

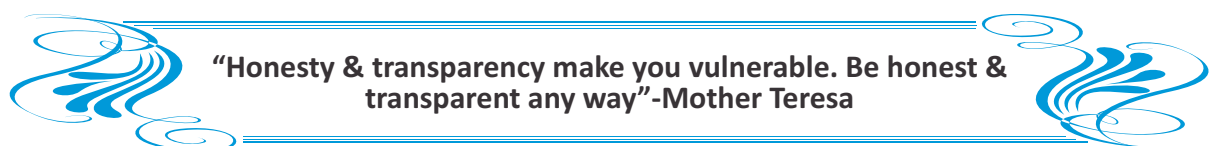
Lesson: Inspecting Engineer should verify the Internal Test Reports minutely and send the lab test request according to the requirements of Purchase Order.

Wrong reporting by out side lab

In a case of inspection, it was observed that lab where samples of textile item (drawn by Inspecting Engineer) were got tested, had done wrong reporting which resulted in supply of sub standard material. During investigation it emerged that the consignee had sent samples to two different labs and both the test results were found to be non conforming to the relevant specifications. Thereafter, counter samples kept in RITES Lab were got tested from another lab and the results were again found non conforming.

The outcome of the investigation resulted in delisting of the outside lab which reported wrongly causing sub standard material to be passed.

Lesson: Secrecy of sample testing lab should be maintained. Credibility of the external labs must be checked from time to time.



जाली आंतरिक रिपोर्ट तथा अनुचित प्रयोगशाला परीक्षण अनुरोध

एक निवारक जांच में यह पाया गया कि आपूर्तिकर्ता ने निरीक्षण इंजीनियर को जाली आंतरिक जांच रिपोर्ट सौंपी तथा निरीक्षण इंजीनियर ने आंतरिक जांच रिपोर्ट की बिना समीक्षा किए ही निरीक्षण कर दिया. इसके पश्चात नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया था. निरीक्षण इंजीनियर ने प्रयोगशाला को लिखे गए जांच अनुरोध पत्र में पीओ के अनुसार किए जाने वाले सभी परीक्षणों को अंकित नहीं किया था. इस प्रकार निरीक्षण इंजीनियर ने लापरवाही से निरीक्षण करते हुए घटिया सामग्री को स्वीकार किया था.

सीख : निरीक्षण इंजीनियर को परीक्षण रिपोर्टों की बारीकी से जांच करनी चाहिए तथा क्रय आदेश की अपेक्षाओं के अनुसार ही प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अनुरोध पत्र भेजना चाहिए.

बाहरी प्रयोगशाला द्वारा गलत रिपोर्टिंग

निरीक्षण के एक मामले में यह देखा गया है कि टेक्सटाइल मर्चें के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण इंजीनियर द्वारा लिए गए नमूनों का परीक्षण प्रयोगशाला में करवाया गया जिसने गलत रिपोर्टिंग की. इसके परिणामस्वरूप क्रेता को घटिया सामग्री की आपूर्ति की गई. जांच के दौरान यह सामने आया कि क्रेता ने निरीक्षण के उपरांत प्राप्त सामग्री से दो नमूने अलग-अलग प्रयोगशालाओं में भेजे, दोनों जांचों के परिणाम संगत विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाए गए. इसके पश्चात राइट्स प्रयोगशाला में रखे गए काउंटर नमूनों की एक अन्य प्रयोगशाला में जांच करवाई गई तथा परिणाम फिर से गैर-अनुरूप ही पाए गए. जांच के नतीजे के परिणामस्वरूप बाहरी प्रयोगशाला को राइट्स की स्वीकृत सूची से हटा दिया गया जिसने गलत तरीके से रिपोर्ट किया था और परिणामस्वरूप घटिया सामग्री पारित हो गई थी.

सीख : नमूना परीक्षण प्रयोगशाला की गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए. बाहरी प्रयोगशालाओं की विश्वसनीयता की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए.

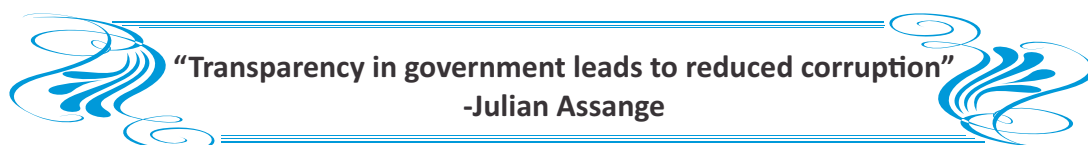


Irregularity in inspection of track items

In a preventive check, it came to notice that Inspecting Engineer had accepted the track material without firm's markings on it. Further, he did not check the chemical composition and physical properties of the material. Track items mentioned above included special bearing plates, slide chairs, Tie Plates, Leading Stretcher Bar. IE had passed 447 Sets of switches and crossings in different lots without checking the chemical composition of material.

Lessons : (i) Marking as required by the Purchase Order should be properly verified.

(ii) Chemical composition and physical properties must be checked as per governing specification/approved QAP.

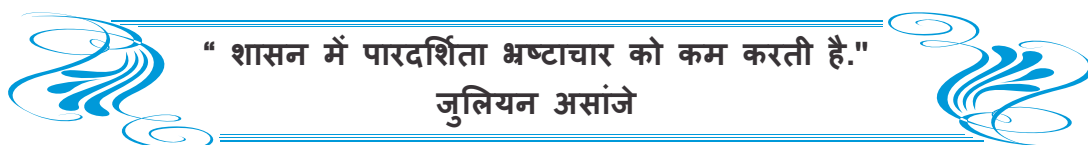


ट्रैक मर्दों के निरीक्षण में अनियमितता

एक निवारक जांच में यह पाया गया कि निरीक्षण इंजीनियर ने फर्म की मार्किंग के बिना ही ट्रैक सामग्री को स्वीकार कर लिया था. साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने सामग्री की रासायनिक संरचना और भौतिक गुणों की जांच भी नहीं की. (उपर्युक्त ट्रैक मर्दों में विशेष बियरिंग प्लेटें, स्लाइड चेयर, टाई प्लेट्स, लीडिंग स्ट्रेचर बार शामिल हैं). निरीक्षण इंजीनियर ने सामग्री की रासायनिक संरचना एवं भौतिक गुणों की जाँच किए बिना अलग-अलग लॉटों में ४४७ सेट स्विच और क्रॉसिंग पारित किए थे.

सीख : (i) क्रय आदेशानुसार मार्किंग उपयुक्त रूप से निरीक्षित एवं स्वीकृत सामग्री पर लगी होनी चाहिए.

(ii) रासायनिक संरचना एवं भौतिक गुणों की जाँच लागू विनिर्देश / अनुमोदित क्यूएपी के अनुसार होनी चाहिए.



SYSTEM IMPROVEMENTS RESULTING FROM PROJECT EXECUTION

SYSTEM IMPROVEMENT NO-1

During inspection at project sites, it has been observed that the strength of concrete cubes observed during testing was much more than the strength required for specified grade of concrete. Accordingly, it has been suggested for issuance of instructions to properly check the cement content as against the required strength of concrete. As a system improvement, Contract policy cell has issued instruction that concrete mix design obtained from engineering college/research laboratory etc. should be tested at site and modified suitably, if required, so as to obtain the specified strength in an economical manner.

SYSTEM IMPROVEMENT NO-2

During one of the CTE type examinations, it had been observed that the documents, as stipulated in Section 24.7 (check list for check at SBU Office before passing of bill) of RITES CPM Guidelines, which should accompany the RA Bills, were not found enclosed with the bill. As a system improvement, Contract policy cell has reiterated instructions regarding list of documents which should accompany running account bills and final bills. It should be ensured that the specified documents as given at Annexure-24.4 and 24.5 of RITES CPM Guidelines are enclosed with the contractor's bills.



परियोजना निष्पादन के परिणामस्वरूप प्रणालीगत सुधार

प्रणालीगत सुधार सं. - 1

परियोजना साइट पर निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि परीक्षण में कंक्रीट क्यूब की क्षमता विशिष्ट ग्रेड के लिए आवश्यक कंक्रीट की क्षमता से अधिक थी. तदनुसार, कंक्रीट की अपेक्षित क्षमता के अनुरूप सीमेंट की मात्रा को ठीक तरह से जांचने के निर्देश जारी करने का सुझाव दिया गया. प्रणाली में सुधार के रूप में अनुबंध नीति विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज / शोध प्रयोगशाला आदि से प्राप्त कंक्रीट मिश्रण डिजाइन का साइट पर परीक्षण किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उचित रूप से संशोधित किया जाए, ताकि किफायती रूप से निर्दिष्ट क्षमता प्राप्त की जा सके।

प्रणालीगत सुधार सं. - 2

सीटीई जांच के दौरान राइट्स सीपीएम दिशानिर्देशों के सेक्शन 24.7 (बिल पारित करने से पूर्व एसबीयू कार्यालय में जाँच के लिए जाँच सूची) में निर्धारित दस्तावेज, जो आरए बिलों के साथ लगे होने चाहिए, बिल के साथ संलग्न नहीं थे. प्रणाली में सुधार के रूप में, अनुबंध नीति विभाग ने दस्तावेजों की सूची के संबंध में निर्देशों को दोहराया है जो चल (रनिंग) खाता बिलों और अंतिम बिलों के साथ होने चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राइट्स सीपीएम दिशानिर्देशों के अनुलग्नक -२४.४ और २४.५ के अनुसार विनिर्दिष्ट दस्तावेज ठेकेदार के बिलों के साथ संलग्न हैं

“यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं.”


- मार्क ट्वेन

SYSTEM IMPROVEMENT NO - 3


During one of the CTE type examinations, it has been observed that payment of one RA bill which contained payment of mobilization advance was released to the contractor while confirmation of extension of Bank Guarantee submitted for mobilization advance was not received. As a system improvement, Contract policy cell has reiterated instructions with regard to release of payment under cl.1A, 5(b) and 10B of GCC. Further, a close watch needs to be kept on the validity of the Bank Guarantees and their extension if required.

SYSTEM IMPROVEMENT NO - 4

During one of the CTE type examinations, it had been observed that necessary amount to be withheld for non-achievement of milestones by contractor as given in Schedule-F in the contract was not withheld. As a system improvement, Contract policy cell has reiterated instructions that in case of non-achievement of milestones by the contractor, the amounts specified in Schedule-F of contract shall be withheld. It must, therefore, be ensured that in case a contractor fails to achieve a specified milestone, the amount mentioned in Schedule 'F' is withheld without fail from his bill.



“Integrity without knowledge is weak and useless and knowledge without integrity is dangerous and dreadful”-Samual Johnson



प्रणालीगत सुधार सं. - 3

एक सीटीई प्रकार जांच के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदार को जुटाव (मोबिलाइजेशन) अग्रिम से संबंधित एक आरए बिल का भुगतान कर दिया गया था जबकि जुटाव अग्रिम के लिए जमा बैंक गारंटी के विस्तार की पुष्टि नहीं की गई थी. एक प्रणालीगत सुधार के रूप में, अनुबंध नीति विभाग ने जीसीसी के खंड 1ए, ५(बी) और १० बी के अंतर्गत जारीकर्ता बैंक द्वारा बैंक गारंटी की पुष्टि मिलने के बाद भुगतान जारी करने के संबंध में निर्देश दोहराए हैं. इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो बैंक गारंटियों की वैधता और उनके विस्तार पर कड़ी नजर रखनी चाहिए.

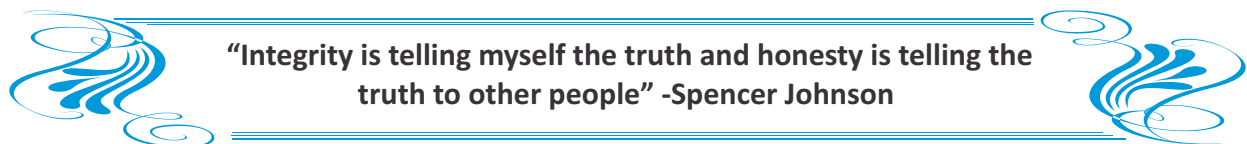
प्रणालीगत सुधार सं. - 4

एक सीटीई प्रकार जांच के दौरान यह पाया गया कि अनुबंध में अनुसूची- एफ में दिए गए निर्देश अनुसार, ठेकेदार द्वारा मील के पत्थरों (निर्धारित लक्ष्यों) को प्राप्त न करने की स्थिति में रोक कर रखी जाने वाली आवश्यक राशि को रोक कर नहीं रखा गया था। प्रणाली के सुधार के रूप में अनुबंध नीति सेल ने निर्देशों को दोहराया है कि ठेकेदार द्वारा मील के पत्थर की प्राप्ति न करने के मामले में अनुबंध की अनुसूची- एफ में निर्दिष्ट राशि को रोक लिया जाएगा। इसलिए, यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई ठेकेदार एक विशिष्ट विनिर्दिष्ट मील का पत्थर हासिल करने में विफल रहता है तो अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित राशि को बिना किसी चूक के उसको भुगतान किए जाने वाले बिल की राशि में से रोक लिया जाए.

ज्ञान के बिना वफादारी कमजोर और बेकार है और बिना वफादारी ज्ञान
खतरनाक और भयावह है " - सैम्युअल जॉनसन


SYSTEM IMPROVEMENT NO - 5

SBU's in RITES dealing with mechanical engineering works are not following RITES CPM Guidelines with an understanding that it is applicable only for civil construction works. It was therefore proposed that instructions be issued to all such SBU's for strict compliance of RITES Guidelines or any other guideline as may be applicable to them while dealing with tendering works. Also the training over invitation and finalization of tenders be provided to officers in all such SBU's. As a system improvement, DT has issued instructions that RITES CPM Guidelines be invariably followed as activities of mostly works contracts/PMC nature are being handled by RW&IE SBU. While the provisions of this manual, which are not relevant, may be discarded but other applicable norms, principles & guidelines be essentially adopted.




प्रणालीगत सुधार सं. - 5

राइट्स में यांत्रिक इंजीनियरिंग कार्यों से संबंधित एसबीयू राइट्स सीपीएम दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका यह मानना है कि यह केवल सिविल निर्माण कार्यों के लिए लागू हैं। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया था कि ऐसे सभी एसबीयू को अनुदेश जारी किए जाएं कि वे निविदा कार्य करने के दौरान राइट्स दिशानिर्देशों या उन पर लागू किन्हीं अन्य दिशानिर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन करें। इसके अलावा, ऐसे सभी एसबीयू में निविदाओं के निमंत्रण और उन्हें अंतिम रूप देने के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। प्रणाली सुधार के रूप में, निदेशक तकनीकी ने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि राइट्स सीपीएम दिशानिर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जाए क्योंकि कार्य अनुबंध / पीएमसी प्रकृति के अधिकतर कार्यकलाप आरडब्ल्यू और आईई एसबीयू द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। हालांकि, इस मैनुअल के प्रावधान, जो प्रासंगिक नहीं हैं, को त्यागा जा सकता है लेकिन अन्य लागू मानदंड, सिद्धांत और दिशानिर्देश अनिवार्यतः अपनाए जाएं।



“सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वयं को जानना और ईमानदारी का अर्थ है कि अन्य लोग भी जानें कि सत्य क्या है” - स्पेन्सर जॉनसन

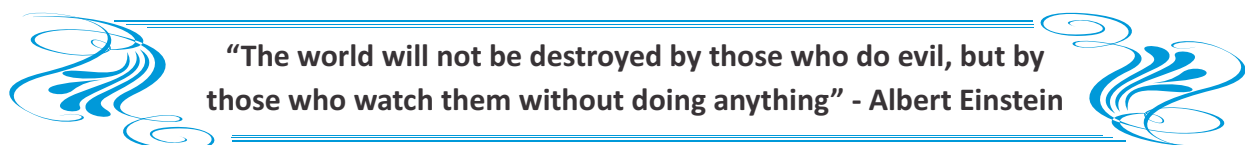


SYSTEM IMPROVEMENTS RESULTING FROM INSPECTION CASES

SYSTEM IMPROVEMENT NO - 6

In a preventive check, it was noticed that in some on-line inspection calls, place of inspection was not indicated as per inspection clause given in the purchase order (PO). Vendor, in the on-line call, had indicated some other place of inspection. Inspecting Engineer failed to check this difference and conducted inspection at the place which was not mentioned in the PO. In the course of investigation, it emerged that Vendor had not uploaded the relevant page of PO (in which place of inspection was indicated) in IBS. In some other cases, it emerged from the PO that purchasers are not mentioning the complete address of manufacturing premises and frequent amendments are being issued regarding change of place of inspection/multiple places of inspection.

In view of above, RITES/Vigilance has recommended to Quality Assurance Division for introducing a system improvement to ensure that while submitting on-line inspection call, vendor should not be able to change the place of inspection and verification of uploaded PO with original PO may be ensured. Quality Assurance Division has issued necessary system improvement.

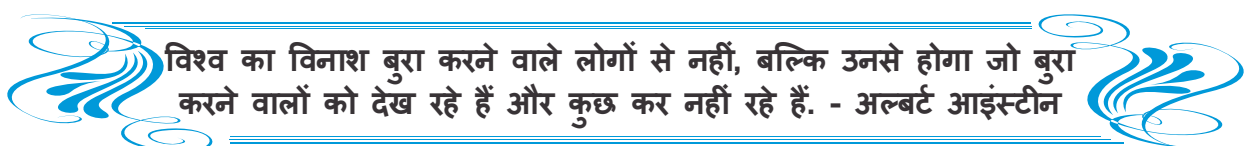


निरीक्षणों के परिणामस्वरूप प्रणालीगत सुधार

प्रणालीगत सुधार सं. - 6

एक निवारक जांच में यह पाया गया कि कुछ ऑन लाइन निरीक्षण कॉल में क्रय आदेश (पीओ) में दिए गए निरीक्षण क्लॉज के अनुसार निरीक्षण का स्थान नहीं दिया गया था। विक्रेता ने ऑन लाइन कॉल में किसी अन्य निरीक्षण स्थल का उल्लेख किया था। निरीक्षण इंजीनियर इस अंतर को देखने में विफल रहा और पीओ में उल्लिखित न की गई जगह पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान यह पाया गया कि विक्रेता ने आईबीएस में पीओ (जिस पृष्ठ में निरीक्षण का स्थान अंकित था) का प्रासंगिक पृष्ठ अपलोड नहीं किया था। कुछ अन्य मामलों में पीओ से यह बात सामने आई है कि खरीददार निर्माण परिसर के पूरा पते का उल्लेख नहीं कर रहे हैं और निरीक्षण के स्थानों/ निरीक्षण के कई स्थानों के परिवर्तन के बारे में क्रेता द्वारा लगातार संशोधन जारी किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए राइट्स/ सतर्कता विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग को प्रणाली में सुधार करने के लिए सिफारिश की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑनलाइन निरीक्षण कॉल प्रस्तुत करते समय निरीक्षण की जगह न बदल सके और अपलोड किए गए पीओ का मूल पीओ के साथ सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग ने प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।



SYSTEM IMPROVEMENT NO - 7

Vigilance had received several complaints regarding supply of underweight Flap Doors. After investigation, it came to notice that RITES Inspecting Engineers are accepting the flap doors without checking the weight. Purchasers are also not mentioning the weight of the flap door in Purchase Order. As a system improvement, RITES/Vig. has recommended to QA Division to issue a standardized check sheet for inspection of flap doors and ask the purchaser to provide the weight of flap door assembly with allowable tolerance.

SYSTEM IMPROVEMENT NO - 8

In a preventive check with regard to inspection of Fabricated Steel Structures (Masts) being supplied to CORE, some of the discrepancies observed are listed below:-

- (i) Firm's markings on each item of steel structure (of masts) is not being done.
- (ii) Actual weight of steel structures is not being checked by Inspecting Engineer (IE).
- (iii) Traceability of stage inspected material with final product is not feasible.
- (iv) Improper Galvanizing of Masts.

In view of above discrepancies, RITES/Vig. has recommended system improvements about marking for item-wise identification and firm's marking on all fabricated steel structures.

To improve galvanizing process, we have recommended to introduce single stage galvanizing by providing long tanks at firm's premises.

For prevention of supply of underweight steel structures, it is recommended to take physical weight instead of calculated weight during inspection.

To ensure traceability of stage inspected material with final product it is recommended to implement a fool proof system. System improvement orders for items (i), (ii) and (iv) mentioned above have been issued. Regarding item (iii), a technically feasible solution is being explored by the Technical Authorities.



प्रणालीगत सुधार सं. - 7

सतर्कता विभाग को कम वजन के फ्लैप दरवाजे की आपूर्ति से संबंधित कई शिकायतें मिलीं। जांच के बाद यह पता चला कि राइट्स निरीक्षण इंजीनियर फ्लैप दरवाजों को उनके वजन की जांच के बिना ही स्वीकार कर रहे हैं। क्रेताओं द्वारा क्रय आदेश में फ्लैप दरवाजे के वजन का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। एक प्रणालीगत सुधार के रूप में राइट्स / सतर्कता विभाग ने क्यूए डिवीजन को फ्लैप दरवाजों के निरीक्षण के लिए एक मानक चेक शीट जारी करने के लिए सिफारिश की है और साथ ही साथ क्रेता को स्वीकार्य अंतर के साथ फ्लैप दरवाजों एसेम्बली का वजन क्रय आदेश में अंकित करने के लिए भी कहा है।

प्रणालीगत सुधार सं. - 8

कोर में आपूर्ति की जा रही स्टील स्ट्रक्चर (मास्ट्स) के निरीक्षण के संबंध में निवारक जांच में कुछ विसंगतियों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है: -

- i. स्टील स्ट्रक्चर के प्रत्येक मद पर फर्म की मार्किंग नहीं की जा रही है।
- ii. निरीक्षण इंजीनियर द्वारा स्टील स्ट्रक्चर के वास्तविक भार की जांच नहीं की जा रही है।
- iii. स्टेज़ निरीक्षित कच्चे माल एवं अंतिम उत्पाद (स्टील स्ट्रक्चर) की तारतम्यता की जांच नहीं हो पा रही है।
- iv. स्टील स्ट्रक्चर की गैल्वनाइजिंग उचित ढंग से नहीं की जा रही है।

उपरोक्त विसंगतियों को देखते हुए राइट्स / सतर्कता विभाग ने मदों के अनुसार स्टील स्ट्रक्चरों पर फर्म की मार्किंग किए जाने के संबंध में सुधार की सिफारिश की है।

गैल्वनाइजिंग प्रक्रिया में सुधार करने के लिए फर्म के परिसर में बड़े टैंकों द्वारा एकल स्टेज गैल्वनाइजिंग शुरू करने की सिफारिश की गई है।

कम वजन वाली स्टील स्ट्रक्चरों की आपूर्ति की रोकथाम के लिए निरीक्षण के दौरान गणनात्मक वजन के बजाय वास्तविक वजन लेने की सिफारिश की गई है।

स्टेज़ निरीक्षित कच्चे माल व अंतिम उत्पाद (गैल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर) की तारतम्यता की जांच के लिए प्रमाणित प्रणाली लागू करने की सिफारिश की है। उपरोक्त उल्लिखित मदों (i), (ii) और (iv) के लिए प्रणाली सुधार आदेश जारी किए गए हैं। मद (iii) के बारे में तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा एक तकनीकी रूप से व्यावहारिक समाधान का पता लगाया जा रहा है।



"सत्य बोलना एक सुंदर कृत्य है, भले ही सत्य स्वयं कुरूप है"

- ग्लेन डंकन




SYSTEM IMPROVEMENT NO - 9


In investigation of a complaint case regarding inspection of 'Rear Cover (for axle box housing)' it came to notice that the Inspecting Engineer had conducted inspection on the basis of old RITES approved check sheet. After investigation, it emerged that RITES/QA Division had not issued the revised check sheet of 'Rear Cover' whereas drawing had already been amended by the consignee and accordingly PO was issued. On recommendation of RITES/Vig RITES/QA Division has issued revised check sheet for inspection of Rear Cover.

SYSTEM IMPROVEMENT NO - 10

RITES/Vig. had received three Complaints regarding supply of sub standard “Retention Tanks”(used in Bio toilet system) to Consignee. During investigation it was observed that concerned IE's (Northern Region, Western Region) had adopted different inspection procedures by prepared inspection and test plan as per their individual understanding. To stop such complaints, RITES/Vig. has recommended to QA Division to implement uniform inspection procedure by introducing standardized check sheets of items being inspected in different inspection Regions. QA Division has issued necessary instructions.



**“With integrity, you have nothing to fear, since you have nothing to hide.
With integrity, you will do the right thing, so you will have no guilt” -Zig Ziglar**




प्रणालीगत सुधार सं. - 9


'रियर कवर्स (एक्सल बॉक्स के लिए)' के निरीक्षण में शिकायत मिलने पर जांच में यह पता चला कि निरीक्षण इंजीनियर ने राइट्स के पुरानी अनुमोदित चेक शीट के आधार पर निरीक्षण किया था. जांच के बाद यह सामने आया है कि राइट्स / क्यूए प्रभाग ने 'रियर कवर' की संशोधित चेक शीट जारी नहीं की थी जबकि क्रेता द्वारा संशोधित ड्राइंग के अनुसार क्रय आदेश जारी किया गया था. राइट्स / सतर्कता विभाग की सिफारिश पर राइट्स / क्यूए प्रभाग ने रियर कवर के निरीक्षण के लिए संशोधित चेक शीट जारी की है।

प्रणालीगत सुधार संख्या. - 10

राइट्स / सतर्कता विभाग को विभिन्न क्रेताओं को घटिया "रिटेंशन टैंक" (बायो टॉयलेट सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला) की आपूर्ति किए जाने से संबंधित तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित निरीक्षण इंजीनियरों ने (उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र) अपनी व्यक्तिगत समझ के अनुसार अलग-अलग तरीके से चेक शीट तैयार करके विभिन्न निरीक्षण प्रक्रियाओं को अपनाया था। ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए, राइट्स / सतर्कता विभाग ने विभिन्न निरीक्षण क्षेत्रों में निरीक्षण की जा रही मर्दों की चेक शीट को मानकीकृत कर एक समान निरीक्षण प्रक्रिया को लागू करने के लिए क्यूए प्रभाग को सिफारिश की है। इस संबंध में क्यूए प्रभाग ने आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।



‘सत्यनिष्ठ होने से आप निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। सत्यनिष्ठ होने से आप सुकर्म करेंगे, इसलिए आपको कोई आत्मग्लानि नहीं होगी।’ - ज़िग ज़िगलर



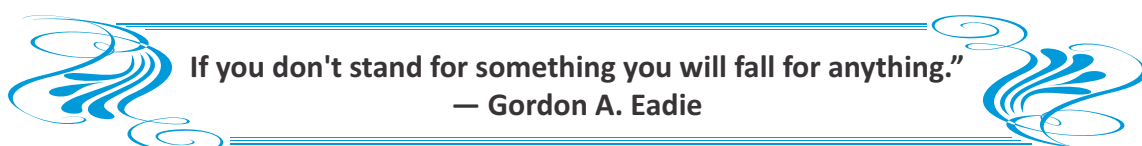
Controlling Corruption in Infrastructure Projects

Arbind Kumar,
Director (Projects)

Introduction:

Corruption is a wide spread curse of our society and is greatly inhibiting desired progress. Transparency International, in 2016, published Corruption Perception Index, ranks India at 79 out of 176 ranks (rank 1 being least corrupt). This indicates that we are somewhere in the middle band but more importantly we have a long way to go to become a corruption free society. We all should contribute in controlling this menace to ensure bright future of our next generation. Government is currently making substantial investment in creation of infrastructure and RITES is being progressively allocated with significant share in implementing transport related infrastructure. It is expected that RITES being a reputed PSU, it would ensure transparency in tendering process, engage competent agencies at most economical price and ensure proper quality. Our proper action can substantially enhance quality and speedy delivery of projects. Such action would greatly enhance RITES' reputation and would result into significant increase in RITES business profile.

RITES has issued detailed Guidelines for the guidance of RITES employees keeping in mind the above objectives in dealing with Project Management of various works. RITES employees have largely developed good understanding in dealing with the contracts and are professionally recognised to be a very competent professional in this field. However, we need to further improve our skill and in this regard suggestions to tackle common errors in a few areas are discussed and suggestions detailed below:



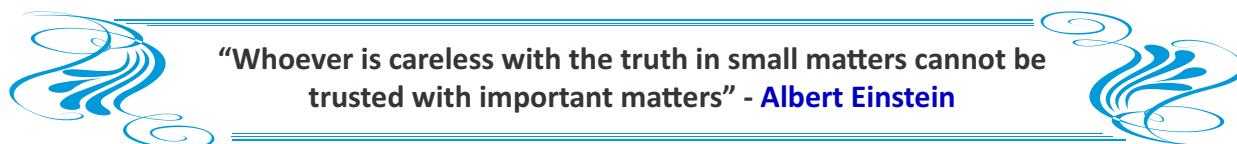
1. **Monitoring Work Schedule and Grant of Extension of Time (EOT):**

The work schedules are not being monitored properly in most of the cases and the same are not being revised periodically to obtain approval of the competent authority. This is a serious lapse which needs to be corrected immediately as both contractor and Project Managers ie.. RITES are responsible to complete the work on time. Project scheduling and monitoring is important to achieve the target. Modern tools of project scheduling should be learnt and used diligently.

Designed format of Hindrance Register is specified at Annexure-20.3 of the Guidelines which should be filled diligently by the site engineers and should be checked by all inspecting officials visiting the site to ensure appropriately filling these registers and working different factors and duration of delays on various accounts with due care. Agency's applications for EOT should be forwarded with proper analysis of various reasons put-forth and analysis of the Hindrance Register having due calculation of delays.

There is a tendency to process EOT only when payment of bills get stuck. Site engineer should initiate EOT well in advance so that payment is made to agencies in time and completion date does not get expired which may create a situation of contract becoming void. There is another tendency that engineers persistently recommend provisional EOT reserving right for imposing LD later, even though Hindrance Register reveals reason for extension very clearly. In this regard clarification has been issued (RITES/CO/CPC/OM dated 09.08.2016 and 21.06.2017) that the previous provisional EOT, if any, has to be subsequently given with due / prior approval of competent authority only.

In a few cases, it is also seen that provisional EOT was issued by Site In-charge / Project Coordinator / Engineer In-charge without getting approval of the competent authority as per Schedule-F of the agreement. It should be clear to all employees that communication should be done with the agencies by the Engineer In-charge after taking due approval from the competent authority.



2. Extra item / substituted item

It has also been observed that cases are put up for approval of Extra Items/ Substituted items after they have already been executed without even obtaining in-principle approval, although this could have been done with the available time period. Site-engineers and engineer-in-charge must obtain prior approval after submission of proposals for Extra Items/ Substituted items with detailed justification.

In case client appoints an architect, RITES engineer shouldn't bypass the architect or influence in taking decisions for change. Further, RITES engineers/project managers should always keep in mind that, we should not do any work which is not technically acceptable or financially justifiable on the pretext that client or architect appointed by client has suggested the same. As a professional consultant we should always ensure that there should not be loss to Govt exchequer and also the purpose of executing such items should not go waste.

3. Variation in Quantity

In some of the cases, it has been observed that works are being executed even beyond the Administrative approval and Expenditure sanction accorded by the client. We are only custodians of client's money and we cannot afford to spend more money than what has been sanctioned/deposited by client. To avoid such situations, revised sanctions should be obtained well in advance from client so that works do not suffer adversely by seeking revised sanction/fund in the 11th hour.

It should always be kept in mind that variation in quantity should be on justifiable grounds arising out of unexpected situations and should not be used as a tool in project management.



4. Inflated Estimate or Low Estimate

Before calling a tender, preparation of estimate of the work is essential. This is most important phase and needs proper care. Making estimate knowingly on much higher side ultimately leads to award of the tender at higher rate as agencies feel that higher rate is easy to get and checks to control quoted price within limits gets defeated. This can be achieved by using standardized rates, as far as possible, as in the case of Standard Schedule of Rates (SOR) published by different departments. Practice of LAR (last accepted rates) are fraught with danger as selective higher LAR can be used to hike the awarded value. Use of appropriate estimate can control corruption effectively in this aspect.

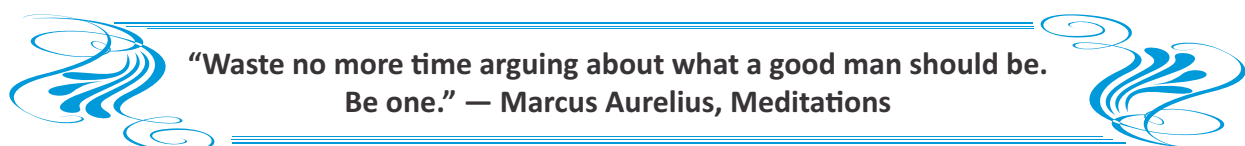
On the other hand, in case of estimate being too lower than reasonable price, it will lead to discharge of the tender leading to loss of valuable time. Lower estimate also leads to lower pre-qualification criteria which can help ineligible bidders to get qualified. Once again such instances can be curbed/ reduced by use of appropriate estimate.

5. Payment of 75% of RA Bills

There is clear provision of payment of 75 % of RA bills within 3 working (excluding day of submission) days of presentation of bill by the contractor in terms of contract and balance 25 % within a period of 15 days of due checks and adjustments. There is a probability of corruption if this clause is not effectively implemented. This clause is for increasing liquidity of agencies to help speedy implementation of projects. Delay in payment of bills not only defeats this purpose but also breeds scope of corruption.

Conclusion

RITES is a reputed Consultancy company having qualified professionals with sound established standards in place and we also have a good opportunity to enhance the growth of the company which can be better achieved, if we propagate honesty and eradicate corruption in our handling of projects.



How to do a Quality Inspection to Avoid Rejection & Complaint

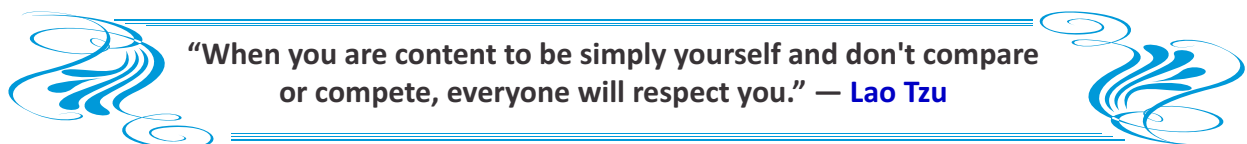
Rajnish Ahuja,
General Manager (QA)/CO

Quality Assurance Division of RITES is carrying out Third Party Inspection of material on behalf of Indian Railways, Public Sector Undertakings, State Govt. departments and many Private organizations. By engaging Third Party Inspection agency, a Purchaser organization expects that the inspected material received by them complies with the Purchase/ Contract/ governing Drawing & Specification requirements and there are no quality issues during production/ usage of it at their end. When the Purchaser is not able to use the inspected material, then a non conformity report in the form of a Rejection Advice/ complaint is received by RITES. Thus a rejection, apart from causing a loss to purchaser and user, also brings disrepute to RITES, and affect it's image and business adversely.

In addition, a Rejection case can always become a Vigilance case depending upon the severity of Complaint/ Rejection as it is always difficult to establish error to be bona fide. The difference between bonafide and malafide intention is very thin and subjective, hence, it is of utmost concern that inspection be done with due alacrity and care to avoid rejection, and consequent difficulty and inconvenience to user and inspection organization.

The probable reasons of Customer Complaints/ Rejections pertaining to Inspecting Engineers are:

- Review of Purchase order, governing drawing and Specification not done properly
- Internal inspection Records not reviewed properly i.e., as per internal records of the Vendor itself, the material is non conforming as per contractual requirements
- Wrong Sampling Techniques
- Incomplete inspection
- Ignorance about the product to be inspected
- Influenced by the Vendor
- Improper Stamping/ Sealing of the material
- Usage of un-calibrated/ Improper instruments during inspection
- Doctored/ biased sample selected for testing at Vendor premises/ an independent lab
- Improper testing of samples by an independent Lab
- Inspection of material carried out at a place other than that mentioned in Purchase order or approved place (as approved by RDSO/ Purchaser)



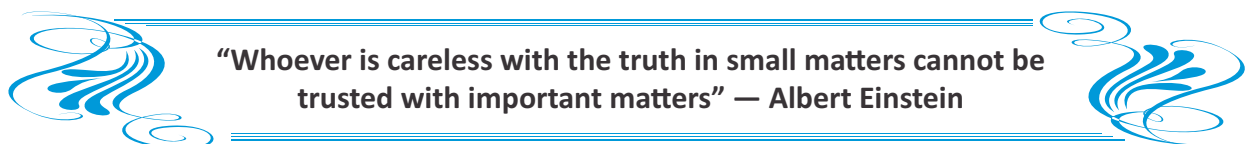
Inspecting Engineers should follow the following for reduction of Rejections and thus a probable Vigilance case:

A. On receipt of Inspection call letter :

- Scrutinize Purchase Order and relevant documents
- Study the Specification/ drawing/ applicable QAP
- Resolve all conflicting and ambiguous requirements before taking up inspection Refer to QAP/Check Sheet as applicable with respect to item under inspection
- Check availability of approved check sheet in IBS
- In case of first time inspection of an item, study all necessary documents to prepare fully for the inspection. Draw check sheet if not already available and get it approved from the Controlling Manager.
- Inspection is to be undertaken at the Place of inspection as stated in the Purchase Order only. For Items listed in RDSO/ICF/ RCF Vendor directories, the inspection is to be carried out only at the Works address stated in these Vendor directories. In case of any discrepancy, IE should contact his Controlling Officer for guidance
- Fix up inspection date with Vendor representative and record the Name of vendor representative and date of contact on Inspection Call letter.
- In case any approved sample has been received from customer, it should be carried to the inspection site

B. At Vendor's premises

- All the documents/information provided by the Vendors like Calibration Certificates, Test Certificates and internal QC Reports as an evidence of quality control by them or by their supplier, are verified for authenticity and conformity to contractual requirements.
- In case of traders, Test certificate from manufacturer should be checked.
- Verify Lot quantity and ensure that complete material as stated in inspection call letter is available
- Conduct thorough visual examination of the offered material
- Ensure Markings as required contractually are available on material/ packages
- Ensure that Packaging of material is as per Contractual requirements
- Examine adequacy of inspection/testing facilities in line with Procedures and environmental controls needed as per inspection/test procedure. Identify tests which can be conducted in the contractor's premises and those which shall have to be tested in outside labs.



Ensure availability of Calibrated instruments & equipments and validity of calibration

- Before starting the inspection, identify the lot appropriately so that no mix-up of the same is possible.
- Select samples from the lot in a random manner and according to applicable sampling plan.
- Identify sample to the lot. In case more than one lot is offered for inspection identification of the sample drawn to the lot shall be ensured.
- Sampling should be done in such a way that each and every item has chance of selection.
- Conduct the Inspection/Testing.
- For destructive testing viz. chemical composition, tensile strength, impact strength, microstructure etc., sampling shall be done differently as per governing specification.
- If Heat or Cast details are not available or relevant, draw samples as per RITES procedure from the lot for conducting the specified destructive tests. Each sample should pass the tests.
- Record all the observations in the check sheet.
- On completion of inspection conducted at the contractor's premises, availing his test facilities, and after having found the consignment acceptable, stamp or affix stickers on the entire material before leaving Vendor's premises. Sealing may be required on packed material.
- Ensure that Sealing/ stamping/ Hologram fixing on material is being done in IE's physical presence

C. For Samples to be drawn for Testing at RITES Lab or independent Lab

- Draw samples and seal/stamp the lot as per procedure. Arrange to deposit the stamped samples for testing/inspection in the Regional office/ approved Lab alongwith the test request.
- Do not take samples suggested by Vendor/ doctored samples
- Ensure that the samples are drawn and identified by RITES identification in IE's physical presence
- Sample drawn for testing should preferably not carry manufacturer's identification mark.
- Ensure that the sufficient sample quantity as required in the specification is submitted to Lab
- For Finished material, if the testing cannot be done on it, then ensure submission of Button/ slab or any other form of sample as per the relevant test requirements
- Test Requisition need not have the name of the final nomenclature of fabricated/ machined product
- Test Requisition submitted to independent lab directly should not have Vendor name and other contractual details



D. After completion of Inspection at Vendor's premises or receipt of Test Reports from independent Laboratory:

- For inspection completed at Vendor's premises, check Completeness of inspection against applicable specification/drawing along with any other requirements of client. In case of multiple visits at Vendor premises for inspection, if the lab test results indicate failure of sample(s), remove/deface the stamp/stickers from the consignment. Generate Inspection Certificate indicating result of inspection i.e., acceptance or rejection, and issue the Inspection Certificate under contractor's acknowledgement.
- On receipt of the test report from RITES Lab/ independent Lab , scrutinize the Test Report for completeness and conformity. If the lab test results indicate failure of sample(s), remove/deface the stamp/stickers from the consignment after visiting Firm premises. Generate Inspection Certificate indicating result of inspection i.e., acceptance or rejection, and issue the Inspection Certificate under contractor's acknowledgement. In case of rejection, issue Inspection Certificate indicating clear reasons for rejection in the appropriate box.

F. Other Points to be taken care of:

- No loose talk at Vendor premises
- Concentrate only on the inspection activities at Vendor premises
- Cancel Inspection call, if complete material is not ready or for other reasons as stated in call cancellation letter
- Take Certificate from Vendor for non dispatch of material to consignee before issue of Inspection Certificate
- Advise Vendor for non shifting of material to some other place
- Advise Vendor about the applicable Testing charges for the samples drawn for testing an independent lab/ RITES Lab by e-mail and request for early submission of the same to RITES
- Take acknowledgement from Vendor's representative for Call Cancellation, Inspection Certificate, Rejection Advice with clear Name, Designation and date of acknowledgement before leaving Vendor premises, if the inspection process is completed at Vendor premises itself
- A scanned copy of Inspection Certificate, Rejection Advice by e-mail should be sent to the Vendor in cases where the Inspection Certificate/ Rejection Advices have to be sent through Courier
- Submit all Inspection documents to office well in time

By following steps above and taking necessary precautions, we can reduce the Consignee Rejections/ Vendor complaints and thus Vigilance complaints.



"Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not." — Oprah Winfrey



Corruption Free India – My Dream

N. Ganesh Babu,

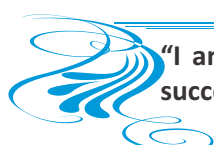
J.G.M.(Airports)

Corruption is commonly perceived as accepting a bribe for doing a work in an unethical manner. The magnitude of corruption varies from top to bottom with authorities of power. The root cause is not always those who are vested with powers demanding a bribe, but we, the common people who instigate to get our work done, bypassing the rules. It is always easy to pass the blame on others but difficult to bring discipline within.


India ranks 79 in the Corruption perception Index 2016. Just imagine India at number 1. How pleasant it would be!. It will be a revolution and revolutions won't happen overnight. We need to make a steady progress towards achieving it.

Literacy make wonders. The future of India hangs in the hands of the youth and the young. The revolution has to start in the schools. Unfortunately, the very place is taunted by corruption. We bribe in the name of donations to get admissions. Tomorrow's leaders of this country start their career by being part of the corrupt system, unknowingly. This has to be stopped. The famous saying by Dr.A.P.J.AbdulKalam “If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher.”

Just imagine a clean India-'Swachhata' in the governance. You don't need to pay any bribe to get your genuine work done. What a great relief that would be to see the country where the quality and merit is respected. Dream India where the 'Netas' work in the interest of the country, the police work for the people, the judiciary deliver fair verdicts, the bureaucrats and the public servants work for the progress of the country – without any malafide intention. That is when we can proudly say '*Sare Jahaan Se Accha*'.



“I am not bound to win, but I am bound to be true. I am not bound to succeed, but I am bound to live up to what light I have.” — Abraham Lincoln

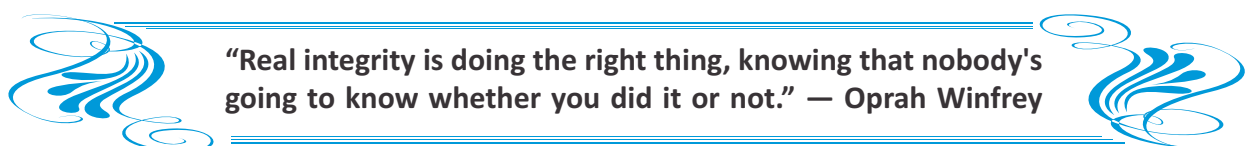


Corruption free India will bring in growth and development. There won't be any need for our own citizens to travel abroad seeking jobs. There won't be spurious drugs in the market and the Government Hospitals won't be the distribution centre of spurious drugs. The roads and buildings of this country will not beg for the bitumen and cement from the contractors. You will pay the right price for your daily needs and get the quality and right amount of quantity in return. There won't be any adulteration. Gone will be those days when the Indians paid money to get a birth or death certificate, electricity connection, gas connection, water connection etc.

Digitization will lead the way. Tax payers will genuinely pay the taxes to the Government, there won't be any income tax watchdogs. There won't be any poverty and there will be parity.

The famous quote from the Bhagwat Gita - "karmanyevadhikaraste ma phalesu kadachana ma karma-phala- heturbhurma tesango 'stvakarmani" provide the guidance. Let not the fruits be the motive of doing your duty. As a common man and a truthful citizen of this country, it is the duty of every citizen to participate in the revolution by taking the pledge not to pay or accept bribe.

The famous quote by Mahatma Gandhiji '*Be the change* that *you wish to see* in the world' is the Mantra.



Corruption in India and Anti-Corruption Efforts

S.K.Singh, DGM/F

Introduction

Corruption in India is an issue that adversely affects the country's economy and the credibility of central, state and local government agencies. Not only has it held the economy back from reaching new heights, but rampant corruption has stunted India's development. Ill effects of corruption have also had adverse impact on the foreign investments.

Corruption has adversely affected some of the development programs and social spending schemes run by the Indian government. Examples include the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and the National Rural Health Mission. Other areas of corruption include India's trucking industry which is forced to pay billions of rupees in bribes annually to numerous regulatory and police stops on interstate highways. The media has widely published allegations of corrupt Indian citizens stashing millions of rupees in Swiss banks.

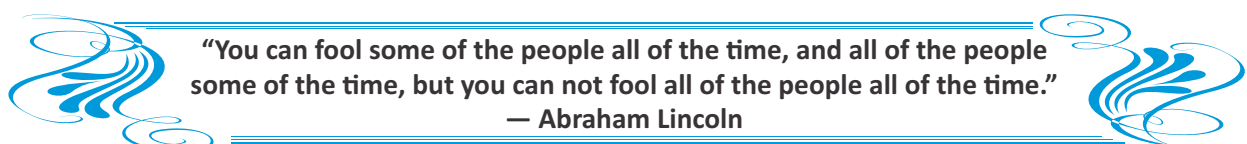
Causes of corruptions

One of the world's largest audit and compliance firms KPMG has noted several issues that encourage corruption in India. The report suggests high taxes and excessive regulation bureaucracy as a major cause; India has high marginal tax rates and numerous regulatory bodies with the power to stop any citizen or business from going about their daily affairs.

The causes of corruption in India include

- excessive regulations,
- complicated tax and licensing systems,
- numerous government departments with opaque bureaucracy and discretionary powers,
- Monopoly of government controlled institutions on certain goods and services delivery,
- Lack of transparent laws and processes.
- Lack of penalties for corruption of public officials
- mandated spending programmes
- Lack of competitive markets

There are significant variations in the level of corruption and in the government's efforts to reduce corruption across different areas of India.



Impact of corruption

Loss of credibility

In a study on Bribery and Corruption in India conducted in 2013 by global professional services firm Ernst & Young (EY), a majority of the survey respondents from PE firms said that a company operating in a sector which is perceived as highly corrupt may lose ground when it comes to fair valuation of its business, as investors bargain hard and factor in the cost of corruption at the time of transaction.

According to a report by KPMG, "high-level corruption and scams are now threatening to derail the country's credibility and [its] economic boom".

Economic loss

Corruption may lead to further bureaucratic delay and inefficiency if corrupted bureaucrats introduce red tape in order to extort more bribes. Such inadequacies in institutional efficiency could affect growth indirectly by lowering the private marginal product of capital and investment rate. Investment rate is a robust determinant of economic growth.

Bureaucratic inefficiency also affects growth directly through misallocation of investments in the economy. Additionally, corruption results in lower economic growth for a given level of income.

Anti-corruption Efforts made in India

Right to Information Act

The Right to Information Act required government officials to provide information requested by citizens or face punitive action. This considerably reduced corruption and opened up avenues to redress grievances.

Right to public services legislation

Right to Public Services legislation, which has been enacted in many states of India, guarantee, time bound delivery of services for various public services rendered by the government to citizen and provides mechanisms for punishing the errant public servant who is deficient in providing the service stipulated under the statute. Right to Service legislation is meant to reduce corruption among the government officials and to increase transparency and public accountability.



"If it is not right do not do it; if it is not true do not say it."
— Marcus Aurelius



Anti-corruption laws in India

Public servants in India can be imprisoned for several years and penalised for corruption under the:

- Indian Penal Code, 1860
- Prosecution section of Income Tax Act, 1961
- The Prevention of Corruption Act, 1988
- The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 to prohibit benami transactions.
- Prevention of Money Laundering Act, 2002

The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 which came into force from 16 January 2014, seeks to provide for the establishment of the institution of Lokpal to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries in India.

Whistle Blowers Protection Act, 2011, which provides a mechanism to investigate alleged corruption and misuse of power by public servants and also protect anyone who exposes alleged wrongdoing in government bodies, projects and offices.

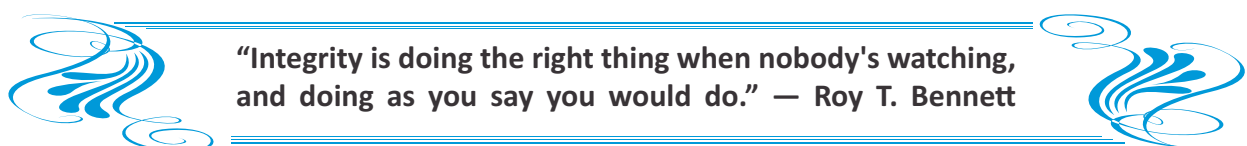
Anti-corruption police and courts

The Directorate General of Income Tax Investigation, Central Vigilance Commission and Central Bureau of Investigation all deal with anti-corruption initiatives. Certain states such as Andhra Pradesh (Anti-Corruption Bureau, Andhra Pradesh) and Karnataka (Lokayukta) also have their own anti-corruption agencies and courts.

Conclusion

We all know corruption in India is like termite and we have to fight against it. Although Government is doing a lot to fight against corruption, but now time has come, where we the citizen of India have to fight against corruption. In our constitution, Democracy is for the people ,by the people and of the people , therefore we the people of India have the capability to fight against corruption.

Recently Government introduced GST with a slogan **“ONE NATION ONE TAX”**. We strongly feel that this slogan should be extended to cover corruption and should read as **“ONE NATION ONE TAX AND ZERO CORRUPTION”**.

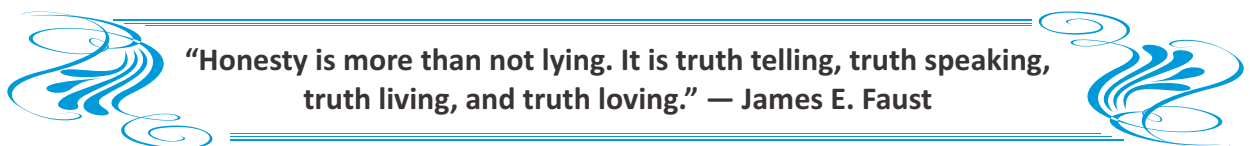


भ्रष्टाचार

मोनिका शर्मा

भ्रष्टाचार एक मायावी दानव,
मुँह खोले दहाड़ रहा।
सुषुप्त अवस्था में सोए हुए,
जन मानस को ललकार रहा॥
इस दानव मुँह के ग्रास बनें,
छोटे पद से लेकर व्यापार।
मीडिया में भी घुस कर बैठा,
न्याय तंत्र पर किया अधिकार॥
आम आदमी से लेकर नेता,
पशुओं का चारा खा जाते,
बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचारी,
कोयले की कालिख तक लगवाते॥
माना किला अभेद्य है इसका,
ब्रह्मास्त्र भी जाये बेकार,
फिर भी हम जन को करना है,
पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार॥
फैला चारों तरफ इसका जाल,

गर लगी न इस पर आज लगाम,
कैसे होगा देश निर्माण॥वीरों की यह कर्मभूमि है,
हम सब हैं इसकी संतान।
आओ कुचल दें इसके फन को,
बनाए अपना देश महान॥
जागरूकता के बिगुल से,
भ्रष्टाचार पर करें मिल प्रहार।
तभी बजेगा अमन का डंका,
और सपने होंगे साकार॥
भ्रष्ट मन जब फुँकार करे,
ईमान का लहू चहुं ओर बहे।
अंतःकरण को अपने तब पाएंगे,
सत्यता को जब अपनाएंगे॥
कब तक नोचोगे इस देश को,
पापी मन को समझाना है।
अब तो भ्रष्ट मुक्त देश बनाएँ,
और भारत को स्वर्ग बनाना है॥




“Honesty is more than not lying. It is truth telling, truth speaking,
truth living, and truth loving.” — James E. Faust


मेरे सपनों का भारत

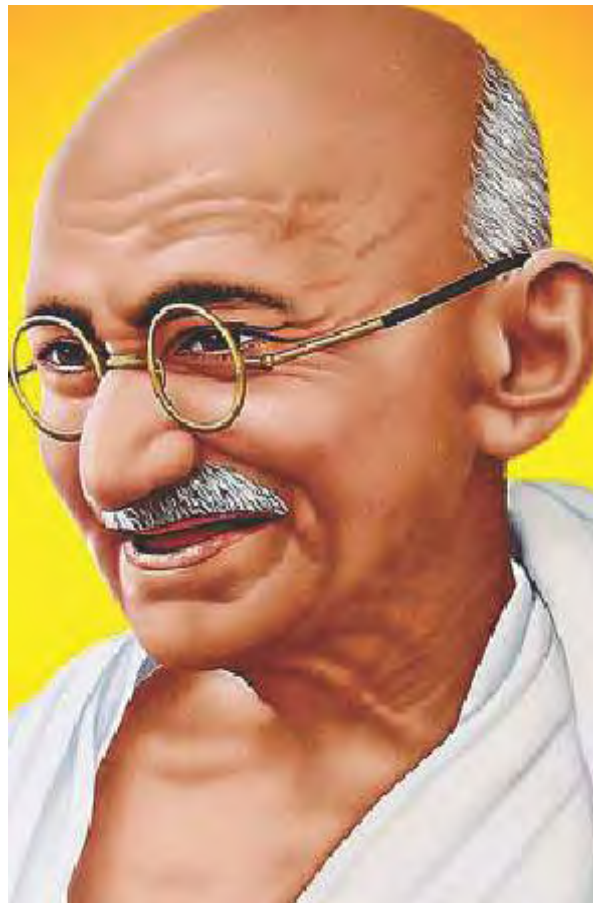
रणबीर सिंह मल्ल
सहायक/सतर्कता

सपनों का भारत अपनों का भारत सुंदर भारत प्यारा भारत
कब होगा, जब होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत
रिश्वत के अर्जन से घर में अंधेरा छा जायेगा
ईमानदारी और मेहनत से ही घर जगमगाएगा
होंगे बच्चे खुशहाल फले फूलेगा इनका जीवन
यश और वैभव की कृति से होंगे ये सुख संपन्न
अनुसरण करें यदि ईमानदारों का तो खुशहाल जीवन बिताओगे
बेईमानी और भ्रष्टाचार से तो बीमारी और कुपूत ही पाओगे
भ्रष्टाचार की कमाई से मांगे बच्चा दस रुपये तो हजार उसे दे दोगे
कहाँ उसने खर्च किए कोई हिसाब न लोगे
इस से होगा क्या, उसमें तामसिक गुणों की प्रवृत्ति जागेगी
समाज में फैलाएगा अन्याय अत्याचार इससे व्याभिचारिता ही आयेगी
जिस प्रकार से सात्विक भोजन करने से सात्विक गुणों का सृजन होता है
उसी प्रकार भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा की गयी अनैतिक कमाई से तामसिक गुणों का
सृजन होता है
अपने अन्दर झाँक कर देखो एक दिव्य शक्ति बैठी होगी
भारत माँ का हर सपूत करे ईमानदारी से कार्य ऐसी ईछा रखती होगी
ईमानदारी और सदाचार से सुविचार है आता
भ्रष्टाचारियों की करतूतों से कुपित है भारत माता
ईमानदारी के ज्ञान दीप से भ्रष्टाचार मिटाओ
सतर्कता जागरूकता सप्ताह में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की जोत जलाओ
सपनों का भारत अपनों का भारत सुंदर भारत प्यारा भारत
कब होगा, जब होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत



“Integrity is telling myself the truth and honesty is telling the truth to other people.” — Spencer Johnson





**"MORALITY IS THE
BASIS OF THINGS
AND TRUTH IS THE
SUBSTANCE OF ALL
MORALITY "**

Mahatma Gandhi

RITES planned to release Special Cover on the occasion of Vigilance Awareness Week-2017 in addition to other activities. In order to finalize the design of Special Cover, Principal of Delhi College Arts was consulted and it was decided to assign the task to students of Masters Degree in Delhi College of Arts. Twenty five students participated and five best entries were selected by a committee comprising of Prof. B.S. Chauhan (HOD, Delhi College of Art), Ms. Ratnabali Kant (Sculptor) and Sh. Shankha Samanta (renowned Painter) as reproduced below. Design made by Ms. Noopur Sharma, which was selected as the best entry has been used for final design of FDC. First day cover will be released on 31.10.2017 during Vigilance Awareness Week-2017 in RITES Office Complex, Gurugram. We appreciate the efforts of judges and students in making this exercise of release of Special Cover successful.



Noopur Sharma



Garima Shokeen



Aanchal Jain



Shalini Gupta



Yogesh Dutt Sharma